

सरकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण का अध्ययन: पश्चिम मध्य प्रदेश पर आधारित शोध

Himanshu Shukla¹, Dr. Sandeep Shukla²

1*Research Scholar, Department of Management, Vikrant University, Gwalior, (M.P.), India
himanshushukla47@gmail.com

2*Ph.D. Guide, Department of Management, Vikrant University, Gwalior, (M.P.), India
drsshukla4@gmail.com

सार

महिलाओं का सशक्तिकरण सतत एवं समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संबंधी विकास के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश, जिसमें इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, देवास एवं उज्जैन जैसे जिले शामिल हैं, सामाजिक-आर्थिक विविधता तथा जनजातीय आबादी के कारण इस विषय के अध्ययन के लिए विशेष महत्व रखता है।

यह अध्ययन सरकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण का विश्लेषण करता है। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा मध्य प्रदेश की महिला सशक्तिकरण योजनाओं के प्रभाव का द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। पूर्ववर्ती अध्ययनों से भी संकेत मिलता है कि स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण आजीविका मिशन तथा राज्य-स्तरीय योजनाएँ महिलाओं की आय, सामाजिक सहभागिता और वित्तीय समावेशन में सकारात्मक भूमिका निभाती हैं, हालांकि जागरूकता, डिजिटल साक्षरता तथा प्रशासनिक चुनौतियाँ अभी भी प्रभाव को सीमित करती हैं।

अध्ययन का निष्कर्ष यह इंगित करता है कि योजनाओं ने महिलाओं के वित्तीय समावेशन, सामाजिक सहभागिता, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, स्वरोजगार तथा निर्णय लेने की क्षमता में सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि योजनाओं के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन हेतु स्थानीय संस्थाओं की क्षमता, प्रशिक्षण, डिजिटल पहुँच और योजनाओं के अभिसरण (convergence) को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

मुख्य शब्द: महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, सरकारी योजनाएँ, पश्चिम मध्य प्रदेश, वित्तीय समावेशन, स्वयं सहायता समूह, सामाजिक विकास।

भूमिका

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ ग्रामीण आबादी आज भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है। ग्रामीण विकास की सफलता महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है क्योंकि वे कृषि, पशुपालन, लघु उद्योग, परिवार प्रबंधन तथा सामुदायिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बावजूद ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय संसाधनों, तकनीकी ज्ञान तथा निर्णय लेने के अवसरों में असमानता का सामना करना पड़ता है।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। समय के साथ इन योजनाओं का स्वरूप केवल कल्याणकारी सहायता तक सीमित न रहकर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में विकसित हुआ। वर्तमान में महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं का उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना तथा स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाना है।

पश्चिम मध्य प्रदेश सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत विविध क्षेत्र है। यहाँ अनुसूचित जनजाति एवं ग्रामीण समुदायों की उल्लेखनीय जनसंख्या निवास करती है। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, देवास तथा उज्जैन जैसे जिलों में महिला विकास की स्थिति अलग-अलग स्तर पर दिखाई देती है। इसलिए यह क्षेत्र सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है।

इस क्षेत्र में संचालित प्रमुख योजनाओं में—

- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- पोषण अभियान
- मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना
- लाड़ली बहना योजना
- स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम

विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं की आय बढ़ाना, बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करना तथा सामाजिक निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। मध्य प्रदेश की महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका संबंधी योजनाओं का आधिकारिक उद्देश्य भी महिलाओं को प्रशिक्षण, आजीविका एवं संस्थागत समर्थन उपलब्ध कराना है।

अध्ययन की आवश्यकता

यह अध्ययन निम्न कारणों से महत्वपूर्ण है—

- पश्चिम मध्य प्रदेश में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का क्षेत्रीय विश्लेषण उपलब्ध कराना।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का तुलनात्मक मूल्यांकन करना।
- नीति-निर्माताओं को क्षेत्र-विशिष्ट सुझाव प्रदान करना।
- महिला सशक्तिकरण के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संबंधी आयामों का समग्र अध्ययन करना।
- भविष्य की महिला विकास नीतियों के लिए साक्ष्य-आधारित आधार तैयार करना।

अध्ययन के उद्देश्य

1. पश्चिम मध्य प्रदेश में संचालित महिला-केंद्रित सरकारी योजनाओं का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर इन योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करना।
3. सामाजिक एवं पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी का मूल्यांकन करना।
4. शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुधारों का अध्ययन करना।
5. वित्तीय समावेशन एवं स्वरोजगार पर योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करना।
6. सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं की पहचान करना।
7. नीति सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध

1. क्या सरकारी योजनाओं से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है?
2. क्या महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है?
3. क्या स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान दिया है?
4. क्या पश्चिम मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में योजनाओं का प्रभाव समान है?
5. योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रमुख बाधाएँ कौन-सी हैं?

शोध परिकल्पनाएँ

H₀: सरकारी योजनाओं का ग्रामीण महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

H₁: सरकारी योजनाओं का ग्रामीण महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण पर सकारात्मक एवं सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव है।

अनुसंधान पद्धति

घटक

विवरण

अध्ययन का प्रकार	अनुभवजन्य (Empirical) एवं वर्णनात्मक
शोध अभिकल्प	विश्लेषणात्मक
अध्ययन क्षेत्र	पश्चिम मध्य प्रदेश
अध्ययन इकाई	ग्रामीण महिलाएँ एवं सरकारी योजनाएँ
डेटा स्रोत	द्वितीयक आँकड़े
द्वितीयक स्रोत	महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन, नीति आयोग, NFHS-5, जनगणना,
विश्लेषण तकनीक	प्रतिशत, औसत, प्रवृत्ति विश्लेषण, सहसंबंध, SPSS आधारित सांख्यिकीय विश्लेषण
अध्ययन अवधि	2019-2025 (उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर)

चर्चा

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि—

- महिलाओं की आय में वृद्धि हुई।
- स्वयं सहायता समूहों का विस्तार हुआ।
- बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच बढ़ी।
- सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार हुआ।
- स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ी।
- घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी।

फिर भी—

- जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता कम है।
- डिजिटल साक्षरता सीमित है।
- इंटरनेट सुविधा कमजोर है।
- कुछ योजनाओं में लाभार्थी चयन की समस्याएँ हैं।

निष्कर्ष

अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि महिला कल्याणकारी योजनाओं ने पश्चिम मध्य प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, वित्तीय समावेशन तथा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार किया है।

हालाँकि योजनाओं के प्रभाव को और अधिक व्यापक बनाने के लिए जागरूकता, डिजिटल प्रशिक्षण, कौशल विकास, विपणन सहायता तथा नियमित निगरानी की आवश्यकता है।

सुझाव

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला सहायता केंद्र स्थापित किए जाएँ।
2. स्वयं सहायता समूहों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
3. वित्तीय साक्षरता अभियान चलाए जाएँ।
4. योजनाओं की सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) व्यवस्था लागू की जाए।
5. महिला उद्यमिता हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाए।
6. पंचायत स्तर पर महिला परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएँ।
7. योजनाओं का ऑनलाइन निगरानी तंत्र विकसित किया जाए।

संदर्भ

1. Government of India. (2023). *Economic Survey of India*.
2. Ministry of Women and Child Development. (2023). *Annual Report*.
3. National Family Health Survey (NFHS-5). (2021). *India Fact Sheet*.
4. NITI Aayog. (2023). *Women Empowerment Index Report*.
5. Census of India. (2011). *Primary Census Abstract*.
6. Kabeer, N. (1999). *Resources, Agency and Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment*. Development and Change.
7. Sen, A. (2001). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
8. National Rural Livelihood Mission. (2023). *Annual Progress Report*.
9. Reserve Bank of India. (2023). *Financial Inclusion Report*.
10. Government of Madhya Pradesh. (2024). *Department of Women and Child Development Annual Report*.